फूलों की सुगंध केवल वायु के साथ फैलती है लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है।
– अज्ञात

गंभीर समस्या की ओर इशारा

देश की प्रमुख जांच एजेंसी को अब राज्य में किसी तरह की खोजबीन शुरू करने से पहले हर केस के लिए अलग से राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का इकलौता नहीं, बल्कि पांचवां राज्य है।

लक्ष्मी अग्रवाल।।

जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच पड़ताल करने के लिए मिली आम इजाजत को वापस लिया है, वह देश में विकसित हो रही एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। देश की प्रमुख जांच एजेंसी को अब राज्य में किसी तरह की खोजबीन शुरू करने से पहले हर केस के लिए अलग से राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का इकलौता नहीं, बल्कि पांचवां राज्य है।

इससे पहले पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी सीबीआई को नो एंट्री का बोर्ड दिखा चुके हैं। केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने वाली एजेंसी सीबीआई को काफी पहले से कहा जा रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट उसे पिंजरे का तोता कह चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकारों का एक–एक कर सीबीआई के कामकाज पर पाबंदियां लगाना एक नया चलन है। सवाल है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया है कि राज्य सरकारें देश की प्रमुख जांच एजेंसी के खिलाफ खड़ी होने को मजबूर हो रही हैं।

एक बहुदलीय लोकतंत्र में केंद्र और राज्यों में अलग–अलग पार्टियों की सरकारें बनना सामान्य बात है। पहले भी ऐसी सरकारें रही हैं और तमाम सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हितों का ख्याल भी रखती रही हैं। लेकिन नमूने के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जिस तरह दो राज्यों की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच टकरावपूर्ण माहौल बना और मुंबई पुलिस को चौतरफा निशाना बनाया गया, उसके बाद भी राज्य और केंद्र की सरकार के बीच भरोसा बना रहता तो इसे एक चमत्कार ही कहा जाता। हालांकि तमाम हो–हल्ले और आरोप–प्रत्यारोप के बाद उस मामले से जुड़े तथ्य मुंबई पुलिस की जांच प्रक्रिया को ही सही साबित करते जान पड़ते हैं। वह प्रकरण अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि टीआरपी घोटाले का नया मामला सामने आ गया।

मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच–पड़ताल शुरू की। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन इसी बीच लखनऊ में टीआरपी की ही गड़बड़ियों की एक और शिकायत आई जिसे आधार बनाकर वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और फिर तुरत–फुरत वह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद यह आशंका तेज हो गई कि सुशांत केस की ही तरह एक बीजेपी शासित प्रदेश के जरिए यह केस भी मुंबई पुलिस से छीनकर सीबीआई को सौंपने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री बयान भी जारी कर चुके हैं कि सरकार के इस फैसले के पीछे मंशा उस कथित साजिश को नाकाम करने की है, क्योंकि राज्य सरकार मुंबई पुलिस को बदनाम करने और उसे अपना सामान्य कामकाज भी न करने देने के प्रयासों पर मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। इन आरोपों की सचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल उस अविश्वास का है जो राजनीतिक दलों तक सीमित न रहकर विभिन्न सरकारों और जांच एजेंसियों के कामकाज को प्रभावित करने लगा है। भरोसा बहाली के इंतजाम जल्दी न हुए तो देश को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

तपस्या

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

एक बार अयोध्या में एक ब्राह्मण के एकलौता पुत्र की मृत्यु हो गयी। तब उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र का शव राजमहल के सामने लेकर आ गया और विलाप करने लगा। श्रीराम ने जब ये देखा तो इसका कारण देवर्षि नारद से पूछा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि अवश्य ही कोई अपात्र आपके राज्य में तपस्या कर रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि निश्चय ही वो कोई शूद्र है जिसके कुकर्म के दंड स्वरुप इस ब्राह्मण का पुत्र मर गया। देवर्षि ने कहा – हे श्रीराम! किसी शूद्र का तप करना तो द्वापर युग में भी विनाशकारी होता है, फिर ये तो त्रेतायुग है। आप इस राज्य के सम्राट हैं अतः ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे ढूंढे और उसके कर्म का समुचित दंड दें।

संपादकीय

पब्लिक है, सब जानती है

राजनीतिक विरासत के नतीजे मिले–जुले रहे हैं। वैसे नई पीढ़ी के नेताओं को जगन मोहन रेड्डी से सबक लेना चाहिए, जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पिता की मौत के बाद विपरीत परिस्थितियों में अपने को न केवल आंध्र प्रदेश की राजनीति में स्थापित किया, बल्कि अपनी खुद की बनाई पार्टी को सत्ता में लाने और मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। ओडिशा में नवीन पटनायक और यूपी में मायावती के भी उदाहरण हैं, जहां उन्होंने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपनी कामयाबी की इबारत लिखी। हरियाणा में देवीलाल की राजनीतिक विरासत तीसरी पीढ़ी तक आते–आते बिखर गई। कई मामलों में जनता का फैसला बहुत दिलचस्प रहा है, जहां किसी एक नेता की विरासत के हक के कई दावेदार खड़े हुए। आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की राजनीतिक विरासत को लेकर उनकी पत्नी लक्ष्मी पार्वती और दामाद चंद्रबाबू नायडू के बीच जंग छिड़ी, तो जनता ने चंद्रबाबू नायडू को उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत के लिए उनके बेटे उद्धव और भतीजे राज के बीच पाला खिंचा, तो बाल ठाकरे के फॉलोअर्स ने उनके बेटे उद्धव को चुना। यूपी में एक क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती है– अपना दल। इसके संस्थापक डॉ. सोने लाल पटेल की मौत के बाद उनकी राजनीतिक विरासत के लिए उनकी पत्नी और उनकी बेटी के बीच जंग छिड़ी। तमिलनाडु में जयललिता की राजनीतिक विरासत पर अगले साल जनता अपना फैसला सुनाएगी।

राजनीतिक विरासत अपने-अपने बेटे को सौंपने का जो काम किया है, उस पर जनता अपनी मुहर लगाती है या नहीं? लोकतंत्र में नेताओं की इच्छाएं ही काफी नहीं होती हैं, उसमें 'लोक' की सहमति जरूरी होती है।

राजनीतिक विरासत

नदीम।।

बिहार का चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए इस बात का भी फैसला होगा कि राज्य में अलग–अलग जमातों की नुमाइंदगी करने वाले दो बड़े नेताओं– लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने–अपने बेटे को सौंपने का जो काम किया है, उस पर जनता अपनी मुहर लगाती है या नहीं? लोकतंत्र में नेताओं की इच्छाएं ही काफी नहीं होती हैं, उसमें 'लोक' की सहमति जरूरी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बेटे होने के चलते चौधरी अजित सिंह अपने पिता चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत के स्वाभाविक वारिस होते और आज की तारीख में वे उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान नेता होते। लेकिन 'लोक' के जरिए ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। वे वेस्ट यूपी के कुछ गिने–चुने जिलों के, वह भी एक खास जाति के ही नेता बन सके, और आज की तारीख में उन जिलों में भी उन्हें अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है।

बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, दोनों के राजनीतिक जीवन का यह पहला चुनाव होगा, जिसमें वे अपनी पार्टी का चेहरा बनकर और अपने–अपने पिता की राजनीतिक विरासत

की छतरी लगाकर चुनावी मैदान में हैं। दोनों के पिताओं ने अपने बेटों को घोषित तौर पर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है। दोनों ही युवा हैं, और संयोग यह कि दोनों ही राजनीति से हटकर अपना करियर चुनना चाहते थे। तेजस्वी की इच्छा जहां क्रिकेटर बनने की थी, वहीं चिराग बॉलिवुड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। पिता होने के चलते लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने तमाम कोशिश भी कीं कि उनके बेटे अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। लेकिन उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसकी उम्मीद वे कर रहे थे। ऐसे में उन्हें अपने बेटों को राजनीति में आने और भविष्य में राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए राजी करना पड़ा। लालू के जेल जाने के बाद तेजस्वी उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हुए। उधर अपने खराब होते हुए स्वास्थ्य को देखकर रामविलास पासवान समझ गए थे कि उनकी जिंदगी बहुत दिनों की नहीं है। ऐसे में उन्होंने पिछले साल नवंबर में ही चिराग को पार्टी की कमान सौंप दी थी।

राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बनना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा गया है कि कोई नेता जिस 'वोट बैंक' का 'मालिक' होता है, वह 'वोट बैंक' उसके उत्तराधिकारी को अपने आप ट्रांसफर हो गया हो। दरअसल राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए मुश्किल की शुरुआत यहीं से होती है। नेता की जिन खूबियों की बदौलत उसका 'वोट बैंक' तैयार होता है, वह 'वोट बैंक' उन्हीं खूबियों को उसके उत्तराधिकारी में भी कदम दर कदम तलाश करता है। वह उत्तराधिकारी को भी उसी कसौटी पर कसना चाहता है, जिस पर कस कर उसने किसी राजनीतिक शख्सियत को अपना नेता स्वीकारा था। ऐसे बहुत सारे मानक होते हैं जो भले ऑन रिकॉर्ड किसी को दिखाई न पड़ें लेकिन 'लोक' के जेहन में वे चल रहे होते हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव की जन सभाओं में आज भी यह नारा गूंजता है, 'धरती पुत्र मुलायम सिंह', 'जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है।' लेकिन यह नारा अभी अखिलेश यादव की सभाओं में नहीं सुनाई पड़ता है।

सूडोकु नवताल- 5513

मध्यम

9		2		4	1	7		
1						6		
5	7	3	2				4	
				9	4	8		
4		7				9		6
		5	8	3				
	3				6	5	9	1
		6						7
		9	1	8		2		4

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5512 का हल

5	4	9	1	8	3	2	6	7
1	2	6	4	9	7	3	5	8
3	8	7	5	2	6	1	4	9
6	7	1	3	4	2	8	9	5
9	5	3	6	1	8	7	2	4
2	6	4	7	5	9	8	1	3
4	3	5	2	7	1	9	8	6
6	9	2	8	3	4	5	7	1
7	1	8	9	6	5	4	3	2

अपना ब्लॉग

कसौटियों से गुजरना होगा

मोहन। जाहिर सी बात है कि बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को भी इसी तरह की कसौटियों से गुजरना होगा। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान यूं ही इतने बड़े कद के नेता नहीं बन गए थे और न ही कुछ दिन या कुछ महीने में उन्होंने अपना यह जनाधार तैयार किया था। वे एक लंबे सफर के बाद यहां तक पहुंचे। तेजस्वी और चिराग को अपना जनाधार तैयार करने के लिए वह मेहनत तो नहीं करनी होगी, जो उनके पिताओं ने की थी। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि मिले हुए जनाधार को सहेज कर रख पाना, कहीं बड़ी चुनौती होती है। उनके वोट बैंक का फैसला बेटी अनुप्रिया पटेल के पक्ष में गया, जो कि मोदी की 2014–19 की सरकार में केंद्रीय मंत्री रही हैं और इस वक्त भी उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है।